साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

# देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 155 | जौनपुर, शुक्रवार, 01 मार्च 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

## संक्षिप्त खबरें

### एक वाहन, एक फास्टैग को लागू करने की समय सीमा मार्च अंत तक बढ़ने की संभावना

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी एक वाहन, एक फास्टैग पहल को लागू करने की समय सीमा बढ़ा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं को देखते हुए इसकी समय सीमा मार्च के अंत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। एनएचएआई ने इससे पहले एक मार्च से एक वाहन, एक फास्टैग पहल को लागू करने की बात कही थी। अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, पेटीएम संकट को देखते हुए, फास्टैग उपयोगकर्ताओं को एक वाहन–एक फास्टैग मानक अपनाने के लिए अधिक समय दिया जा सकता है। राजमार्गों का प्रबंधन करने वाले निकाय एनएचएआई ने इससे पहले एक वाहन– एक फास्टैग पहल को लागू करने और अपने फास्टैग के लिए केवाईसी को अपडेट करने की समय सीमा 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी थी। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए एनएचएआई ने 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल लागू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने को हतोत्साहित करना है।

### सरकार ने 2024–25 के सत्र के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 3–3.2 करोड़ टन तय किया

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने 2024–25 रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य तीन से 3.2 करोड़ टन तय किया है। खाद्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सरकार के गेहूं खरीद के लक्ष्य को कुछ कम माना जा रहा है। कृषि मंत्रालय को फसल वर्ष 2023–24 (जुलाई–जून) में 11.4–11.5 करोड़ टन के रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की उम्मीद है। इसके बावजूद सरकार द्वारा खरीद का लक्ष्य कम रखा गया है। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ विचार–विमर्श के बाद यह लक्ष्य तय किया गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा, ''विचार–विमर्श के बाद आगामी रबी विपणन सत्र 2024–25 के दौरान गेहूं की खरीद का अनुमान तीन से 3.2 करोड़ टन का तय किया गया है।'' गेहूं के अलावा, मंत्रालय ने चावल के मामले में रबी धान खरीद का लक्ष्य 90 लाख से एक करोड़ टन तय किया है। सरकार ने रबी मोटे अनाज/बाजरा (श्रीअन्न) के लिए 6,00,000 टन का खरीद लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बैठक में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फसलों के विविधीकरण और आहार में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है।

## जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश - मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ, संवाददाता। संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की भूमिका से सभी भलीभांति परिचित हैं। इसी को ध्यान में रखकर वर्ष 1944 में प्रदेश में विभाग का गठन किया गया। वर्ष 1944 से 2017 के बीच 73 वर्षों में केवल 288 फायर स्टेशन स्थापित किये गये जबकि पिछले 7 वर्षों में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए गये। आज हम प्रदेश में तेजी के साथ तहसील स्तर पर एक–एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश पूरे देश में ऐसा राज्य होगा, जहां तहसील स्तर पर फायर स्टेशन होंगे। हमने कानून व्यवस्था में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है साथ ही उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। उसी का परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। हमने विभाग की सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपये दिये हैं। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित अग्निशमन सुरक्षा कवच के सुदृढ़ीकरण के लिए 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण शिलान्यास एवं 35 अग्निशमन वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में कही। इस दौरान सीएम योगी ने विभाग की ओर से लगाई गयी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और अधिकारियों से अग्निशमन उपकरणों की जानकारी हासिल की।

महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले सात वर्षों में विभाग के आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं साथ ही समयबद्ध तरीके से विभाग में अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके परिणाम सभी के सामने हैं। पहले अक्सर उद्यमी एनओसी को लेकर शिकायतें करते थे। हमने उसमें कई बदलाव कर उसे सरल किया। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि फायर टेंडर के रिस्पांस टाइम को कम से कम करने पर जोर होना चाहिये ताकि जन–धन की हानि को कम से कम किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी सुधार भी हुआ है। यही वजह है कि 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया। साथ ही 5000 से अधिक पशुओं के साथ ही 150 करोड़ रुपये की संपत्ति को नष्ट होने से बचाया गया। इसके अलावा विभाग तेज लू के दौरान फसलों में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए सदैव खड़ा रहता है। इसे ही ध्यान में रखते हुए हमने आपात सेवाओं का उच्चीकरण करने का कार्य किया है। इस दिशा में न केवल अग्नि शमन सेवाओं के आधुनिकरण बल्कि प्रदेश में एसडीआरएफ के गठन की कार्रवाई को भी पूरा किया गया है। आज एसडी आरएफ की छह कंपनियां काम कर रही हैं। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करते हुए महत्वपूर्ण इमारतों और संस्थाओं की सुरक्षा के दायित्व को पूरा किया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशवासियों, निवेशकों और टूरिस्ट के विश्वास को और मजबूत करना है। इसी के तहत पहले चरण में जनपद स्तर और दूसरे चरण में तहसील स्तर पर एक से डेढ़ वर्ष में फायर स्टेशन स्थापित हो जाएंगे। आदित्यनाथ ने कहा कि विभाग रिस्पांस टाइम को कम करता है तो कॉमन मैन के मन में विभाग और शासन के प्रति विश्वास मजबूत होगा। उसके लिए सहायता को पहुंचाना हमारा दायित्व है। हमें स्कूल और कॉलेज में बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रयास करना चाहिए, उनकी काउंसिलिंग को भी कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि सामान्य दिनों में केवल विभाग के भरोसे ही रहकर नहीं बल्कि घटना घटित होते ही बचाव शुरू हो यह महत्वपूर्ण है। बचाव के लिए हम लोगों को पहले से ही तैयार करें। अग्निकांड के लिए कौन–कौन सी लापरवाही जिम्मेदार होती हैं, कैसे हम जनधन की हानि को रोक सकें, इसके प्रति लोगों को पहले से तैयार कर सकें तो घटना के बाद जब तक सहायता पहुंचती है तब तक लोग स्वयं भी अपने स्तर पर बचाव अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। हर घटना हमारे लिए एक सबक होनी चाहिए और फिर उस सबक को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लापरवाही से बचा जा सके। सीएम ने कहा कि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो अक्सर लोग वहां पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते रहते हैं। उस समय हमें सबसे पहले वहां पर लोगों को बचाना चाहिए।

## विरासत और विकास को एक साथ लेकर चल रही हमारी सरकार - पीएम मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका उदाहरण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। उन्होंने कहा कि उज्जैन की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं मिली हैं। ये परियोजनाएं उज्जैन के लोगों का जीवन आसान बनाएंगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएंगी। इन परियोजनाओं के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत के कई राज्यों ने विकसित बनने का संकल्प लिया है क्योंकि विकसित राज्यों से ही विकसित भारत बनेगा। आज मध्य प्रदेश इस संकल्प में हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है– अबकी बार 400 पार! पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा भाजपा ने नहीं, बल्कि देश की जनता– जनार्दन का दिया हुआ है। मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव–विभोर करने वाला है।

## निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश अपने आप रद्द नहीं हो सकते – सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि दीवानी और आपराधिक मामलों में निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश छह माह के बाद आपने आप रद्द नहीं हो सकते। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच–सदस्यीय संविधान पीठ 2018 के अपने उस फैसले से सहमत नहीं हुई, जिसमें कहा गया था कि निचली अदालतों के स्थगन आदेश अपने आप रद्द हो जाने चाहिए, जब तक कि उसे विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।

फैसले में (इस विषय पर) दिशानिर्देश जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि संवैधानिक अदालतों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए और ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। पीठ ने दो अलग–अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले सुनाये। न्यायमूर्ति ए. एस. ओका ने कहा, ''संवैधानिक अदालतों को मामलों का फैसला करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर के मुद्दे केवल संबंधित अदालतों को ही पता होते हैं और ऐसे आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पारित किए जा सकते हैं। न्यायामूर्ति ओका ने खुद की ओर से तथा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के लिए फैसला लिखा। उन्होंने कहा, ''स्थगन आदेश अपने आप रद्द नहीं हो सकते।'' न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने मामले में एक अलग, लेकिन सहमति वाला फैसला लिखा।

## धामी ने जोड़ा जनजातीय विकास में नया आयाम

देहरादून, संवाददाता। चम्पावत पिथौरागढ़ क्षेत्र में वन राजी, थारु और अत्यंत अल्प ज्ञात कुतलिया बोरा समाज की परंपराओं तथा मान्यताओं का अभिलेखीकरण व मूल्यांकन हेतु आए पूर्व सांसद तरुण विजय ने कहा कि पुष्कर धामी सरकार ने अत्यंत पिछड़े जनजातीय समाज हेतु विकास के नये आयाम स्थापित किए हैं। किसी शासन में सुदूर क्षेत्रस्थ जनजातीय समाज के सांस्कृतिक अभिलेखीकरण और डिजिटलाइजेशन का कार्य नहीं हुआ। पर धामीशासन में यह कार्य प्रारंभ हुआ है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक फलक की सुरक्षा हेतु देश में विशिष्ट है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय का बजट ७० प्रतिशत बढ़ाया उसी तर्ज पर धामी सरकार का भी जनजातीय कल्याण बजट बढ़ाया गया है। विद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान से साक्षात्कार विज्ञान और प्रोद्योगिकी परिषद के द्वारा सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में बालक बालिकाओं के मध्य विज्ञान मेले पहले कभी सुने नहीं जाते थे, पर अब असामान्य

गति से बढ़ रहे हैं। वन राजी, थारु बुक्सा देश के सर्वाधिक चुनौती ग्रस्त बिलुप्तप्रायसमाज हैं। इनकी वन राजी भाषा की संरक्षा और लिपिकरण हेतु उत्तराखण्ड विज्ञान व तकनीकी परिषद के महानिदेशक डॉ दुर्गेश पंत तथा केंद्र सरकार में विज्ञान व प्रोद्योगिकी मंत्रालय के साथ तरुण विजय कार्य कर रहे हैं। इसी हेतु वे ज्योल जीवी पिथौरागढ़ के ग्राम्य प्रवास पर है। डॉ दुर्गेश पंत ने इस दिशा में नवीन पहल का कीर्तिमान भी बनाया है।

## भाजपा की 370 सीटें हैं परंपरागत अनुमान - केंद्रीय मंत्री पुरी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा के 370 से अधिक सीटें जीतने की भविष्यवाणी पर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का परंपरागत अनुमान है और वह कभी भी कुछ भी बढ़ा–चढ़ाकर नहीं कहते हैं। वह लोगों से संपूर्ण जानकारी हासिल करने के बाद ही एक राजनीतिक मुहर लगाते हैं।

भारी बहुमत से जीतेगी भाजपा

केंद्रीय मंत्री पुरी ने एक इंटरव्यू में गुरुवार को कहा कि जनता को मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं से बहुत लाभ हो रहा है। और भाजपा आनेवाले चुनावों में भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री कभी कुछ भी बढ़ा–चढ़ाकर नहीं कहते हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सातों सीटों पर दोनों दलों के कुल वोट मिलाकर भी भाजपा

प्रत्याशियों के मतों से कम ही रहे थे।

लोगों से मिले इनपुट के आधार पर पीएम मोदी करते हैं आकलन

भाजपा नेता ने कहा कि आप और कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में एक–दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयानों में विभिन्न योजनाओं को पूरा करने या लागू करने की लक्षित तिथियां भी बताई हैं। उनके ऐसा कहने के पीछे सतत और गहरा शोध है। वह बहुत लोगों से मिले इनपुट के आधार पर यह आकलन करते हैं। उसके बाद ही वह इन निष्कर्षों पर राजनीतिक मुहर लगाते हैं।

शहरों से आएगा जीडीपी का 75 प्रतिशत योगदान

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने मिरांडा हाउस में एक शोध केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि वर्ष 2050 तक विश्व की दो–तिहाई आबादी शहरों में रहेगी।

यही 21वीं सदी के चलन के मुताबिक 2050 तक भारत की 50 प्रतिशत आबादी या 87.7 करोड़ देशवासी शहरों में ही रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हमारे जीडीपी का 75 प्रतिशत योगदान हमारे शहरों से ही आएगा।

## दिल्ली के एल-जी ने 'जल योजना' को लेकर केजरीवाल की आलोचना की

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार की कथित श्जल योजनाश पर आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से कागज का एक टुकड़ा भी उनके संज्ञान में नहीं लाया गया। पत्र इस बात से शुरू होता है कि जल, वित्त और शहरी विकास सहित जल योजना से जुड़े सभी विभाग मुख्यमंत्री के सीधे नियंत्रण में हैं, यानी उपराज्यपाल की भागीदारी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। सक्सेना ने कहा कि योजना के संबंध में न तो आधिकारिक तौर पर और न ही अनौपचारिक रूप से कोई जानकारी उनके संज्ञान में लाई गई है। पत्र में कहा गया है, "डीजेबी (दिल्ली जल बोर्ड) पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है निर्णय लें, दूसरों को दोष न दें। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में 27 लाख जल उपभोक्ता कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख ने अपने बिल का भुगतान नहीं किया है और आपका लक्ष्य उन्हें लाभ पहुंचाना है।" एल–जी ने कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर 10 लाख उपभोक्ताओं के बिल, जुर्माना, एलपीएससी और बकाया माफ करने जैसी किसी बात पर विचार किया जा रहा है, तो शेष 17 लाख उपभोक्ताओं द्वारा किए गए भुगतान, जिन्होंने इतने वर्षों में ईमानदारी से अपने बिलों का भुगतान किया है, की भी प्रतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी चाहिए। सक्सेना ने केजरीवाल के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि उपराज्यपाल योजना को श्श्सफेद झूठश्श और दोष से बचने के पैटर्न का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल पर पीड़ित होने का दिखावा बनाए रखने के लिए लगातार उपराज्यपाल, केंद्र सरकार और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। उपराज्यपाल ने मंत्रियों द्वारा जारी बयानों में घोर विरोधाभास रहने की बात भी कही। एलजी ने कहा, "कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी एक पोस्ट में माननीय मंत्री (यूडी) ने लिए गए निर्णयों का एक कालक्रम गिनाया है।

## विकसित आर्थिकी बनने के लिए हमें मजबूत बनना होगा – जयशंकर

पुणे, एजेंसी। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत को अगले 25 साल तक श्अमृत कालश के दौरान ताकत बढ़ानी होगी ताकि देश विकसित आर्थिकी और महाशक्ति बन सके। पुणे में आयोजित एशिया इकोनमिक डायलाग में वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले दशक में मोदी सरकार का दृष्टिकोण और उसके कार्यक्रमों का उद्देश्य राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना रहा है। कोरोना संकट के संदर्भ में जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली ने दुनिया को दिखाया कि वह न केवल अपनी देखभाल कर सकती है, बल्कि जरूरत के समय दुनिया को भी बचा सकती है। ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना को लेकर भारत ने 100 देशों को टीके और अन्य जीवन रक्षक दवाएं भेजीं। विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने मौजूद विभिन्न भू–राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा की। सीमित संख्या में आपूर्तिकर्ताओं

पर निर्भरता, प्रौद्योगिकी की चुनौतियों और बाजार के प्रभुत्व के खतरों को चिह्नित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं दूसरों की सद्भावना से निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने कहा, आपूर्ति–श्रृंखला चुनौती है। दुनिया कुछ ही आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से मुक्त करने के लिए हम सभी को अधिक विकल्पों की आवश्यकता है।

# संपादकीय

## यूक्रेन को बढ़त

पूर्वी यूक्रेन में अव्दिक्का (युद्ध–पूर्व की आबादी – 32,000) का अवर्णनीय शहर इस साल 17 फरवरी को इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया, जब रूसी अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने युद्ध के महीनों में सबसे महत्वपूर्ण सफलता में शहर में प्रवेश किया। घिरे हुए यूक्रेनी सैनिक अव्यवस्थित तरीके से पीछे हटते हुए शहर से भाग गए, जिससे उनके सैकड़ों घायल हो गए और अनगिनत लोग भागने में असमर्थ हो गए। अवदीव्का पर रूस के कब्जे से पश्चिमी राजधानियों में सदमे की लहर दौड़ गई और इस प्रचार को झटका लगा कि रूस धीरे–धीरे यूक्रेन में युद्ध हार रहा है। मई 2023 में रूसी सेनाओं द्वारा बखमुत शहर पर कब्जा करने के बाद से यह युद्धक्षेत्र की जीत सबसे महत्वपूर्ण थी। पिछले साल के असफल ग्रीष्मकालीन जवाबी हमले और 1,000 किलोमीटर चौड़ी सीमा रेखा पर जारी रूसी दबाव के बाद आने वाली नवीनतम यूक्रेनी वापसी ने सुझाव दिया कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही थीं। कीव के लाभ के लिए. विजयी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अवदीवका पर कब्जा करने की सराहना की और यूक्रेन में आगे बढ़ने का वादा किया। इन असफलताओं पर पश्चिमी प्रतिक्रिया, जो रूसी आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ (24 फरवरी) से ठीक एक सप्ताह पहले आई थी, उन्मादी के करीब रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन सहित शीर्ष पश्चिमी नेताओं द्वारा श्री पुतिन को एक अत्याचारी, एक युद्ध अपराधी और ष्पागल एसओबीष् कहा गया है। वाशिंगटन ने रूस पर 600 नए प्रतिबंध लगाए, जो युद्ध की शुरुआत के बाद से अमेरिका द्वारा लगाए गए 4,000 पहले प्रतिबंधों के शीर्ष पर थे। इसी तरह, यूरोपीय संघ ने उन उत्पादों के निर्यात के लिए कई विदेशी कंपनियों और व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए (फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से यह 13वां प्रतिबंध है) जिनका रूस के लिए सैन्य उपयोग हो सकता है। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर का एक सैन्य सहायता पैकेज (अस्थायी रूप से प्रतिनिधि सभा में अटका हुआ) भी पारित कर दिया है। यूरोप ने यूक्रेन के लिए 50 अरब यूरो के चेक पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिमी बैंकों में जमा रूस की 300 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी संपत्तियों को जब्त करने के बारे में भी कुछ बहस हुई है, एक ऐसा कदम जो गंभीर रूप से कमजोर कर देगा। वैश्विक वित्तीय प्रणाली. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यह दावा करके केवल पश्चिमी चिंताओं को हवा दी है कि उनका देश पूरे यूरोप को अपने अधीन करने के श्री पुतिन के दृढ़ संकल्प में पहला कदम है, एक ऐसा आरोप जिसे रूसी राष्ट्रपति ने सख्ती से नकार दिया है। इटली, कनाडा और बेल्जियम के प्रधानमंत्रियों और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष सहित चार शीर्ष पश्चिमी नेता श्री जेलेंस्की के निरंतर युद्ध प्रयासों के साथ एकजुटता की प्रतिज्ञा करने के लिए युद्ध की दूसरी वर्षगांठ पर कीव पहुंचे। कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2.25 अरब डॉलर की वित्तीय और सैन्य सहायता देने का वादा करते हुए घोषणा की, ष्हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, जब तक करना पड़े।ष् इटली की जियोर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन के साथ 10 साल के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए कहाए ष्मैं आज सभी यूक्रेनी लोगों को संदेश देना चाहती हूं कि वे अकेले नहीं हैं। यूक्रेनी और पश्चिमी नेतृत्व द्वारा अपनी एड़ी–चोटी का जोर लगाने और श्री पुतिन की अग्रिम मोर्चों को स्थिर करने और युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने की पेशकश को अस्वीकार करने के साथ, वैश्विक दरार और संबंधित जोखिम केवल बढ़ रहे हैं। फिलहाल, राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने लोकप्रिय शीर्ष सैन्य कमांडर को बर्खास्त करना पड़ा है और हाल के दिनों में हथियारों के सौदे में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप सामने आए हैं, इन दोनों ने सैन्य मनोबल को कम करने में योगदान दिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि युद्ध शुरू होने के बाद से साठ लाख यूक्रेनियन देश छोड़कर भाग गए हैं। पश्चिमी दुष्प्रचार के बावजूद रूसी सेनाएं बैकफुट पर नहीं हैं। वे यूक्रेन के क्षेत्र के लगभग पांचवें हिस्से को नियंत्रित करना जारी रखते हैं, जिसमें प्रमुख क्षेत्रीय शहर डोनेट्स्क भी शामिल है, जिसकी सुरक्षा उत्तर में 15 किमी दूर अवदीवका पर कब्जा करने से मजबूत हुई थी। मॉस्को ने सफलतापूर्वक सैन्य उत्पादन बढ़ाया है और यूक्रेन की तुलना में अधिक तोपखाने के गोले दागने में सक्षम है। यूक्रेनी सैनिक भी थक चुके हैं, जिससे श्री जेलेंस्की को सेना में अतिरिक्त पांच लाख यूक्रेनियनों को भर्ती करने के लिए एक विधेयक लाने के लिए मजबूर होना पड़ा, कुछ लोगों का कहना है कि यह कदम देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगा। रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की पश्चिम की रणनीति काम नहीं आई है। पश्चिम ने अपनी हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए रूसी तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने सहित कई उपाय शामिल किए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ हैय इसके विपरीत, तेल निर्यात युद्ध–पूर्व स्तर के करीब है और आईएमएफ के अनुसार, 2023 में रूस की जीडीपी में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विडंबना यह है कि ऐसा लगता है कि यूरोप को सबसे बुरी आर्थिक मार झेलनी पड़ी है, क्योंकि वह सस्ते रूसी ऊर्जा निर्यात पर निर्भर था। रूसी ऊर्जा के लिए अपने नल को एकतरफा बंद करने के बाद, यूरोप को ऊर्जा की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिसने इसके उद्योग के बड़े हिस्से को अप्रतिस्पर्धी बना दिया है और कृषि लागत आसमान छू रही है।

# वरिष्ठ बाबुओं के लिए जल्द ही लंबा कार्यकाल

आदित्य

पैनल में शामिल लगभग 60 प्रतिशत आईएएस अधिकारियों को सचिव और समकक्ष के रूप में मंजूरी मिल गई है, और उनमें से अधिकांश को पांच साल का कार्यकाल मिल रहा है। यह मोदी सरकार का उच्च–रैंकिंग अधिकारियों को लंबे कार्यकाल प्रदान करने का तरीका है ताकि वे वास्तव में अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से फिट हो सकें।आमतौर पर, रक्षा और गृह सचिवों को केवल दो साल का कार्यकाल मिलता है, जो कुछ वास्तविक कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन बाकियों के लिए, यह एक मिश्रित स्थिति रही है। कुछ बाबू अक्सर इस बात को लेकर शिकायत करते हैं कि जब बड़े निर्णय लेने और काम पूरा करने की बात आती है तो छोटी अवधि के कार्यकाल कैसे बाधा डालते हैं। सूत्रों ने डीकेबी को सूचित किया है कि 1993 बैच के पैनल में शामिल अधिकारियों के नवीनतम समूह में से, 200 में से 12 लंबे समय के लिए पद पर हैं, जिसमें पांच साल से अधिक का समय लगेगा। यहां तक कि 1992 के पूर्ववर्ती बैच के 20 में से पांच आईएएस अधिकारी पांच साल के कार्यकाल पर विचार कर रहे हैं। खबर यह है कि नई सरकार के ड्राइवर की सीट पर बैठते ही हम जून–जुलाई में एक बड़ा बाबू फेरबदल देख सकते हैं। नतीजतन, हाल ही में सूचीबद्ध किए गए कई अधिकारियों को जल्द ही नई पोस्टिंग पर फिर से नियुक्त किए जाने की संभावना है। पूर्व सचिवों ने इस उभरती प्रवृत्ति पर अंतर्दृष्टि प्रदान की है, यह देखते हुए कि सचिवों के लिए पारंपरिक तीन साल का कार्यकाल एक बार पर्याप्त माना जाता था। हालाँकि, परिस्थितियों और प्रशासनिक अनिवार्यताओं ने प्रभावी शासन की सुविधा के लिए लंबे कार्यकाल की ओर बदलाव को प्रेरित किया है। पीएम की सुरक्षा उल्लंघन के दो साल बाद, पंजाब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पीछे चला गया दो साल पहले, जनवरी 2022 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आधे घंटे के लिए एक फ्लाईओवर पर फंसा हुआ था, जब वह पंजाब में यात्रा कर रहे थे, क्योंकि 300 प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने फ्लाईओवर को अवरुद्ध कर दिया था। सुरक्षा उल्लंघन ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। उस समय राज्य सरकार का नेतृत्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे थे। बाद में इंदु मल्होत्रा समिति द्वारा की गई जांच में सुरक्षा उल्लंघन के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई। अब, भगवंत मान की पंजाब सरकार ने पुलिसवालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। कटघरे में खड़े अधिकारियों में पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, तत्कालीन फरीदकोट डीआइजी इंदरबीर सिंह और फिरोजपुर के पूर्व एसएसपी हरमनबीर सिंह हंस शामिल हैं। जबकि श्री चट्टोपाध्याय अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और हुक से बाहर हो सकते हैं, श्री मान अन्य दो के खिलाफ आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, दोनों को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। जांच समिति नियुक्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने पंजाब से एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। जानकार लोगों का कहना है कि फंसे हुए अधिकारी कलाई पर तमाचे से लेकर सेवा से बर्खास्तगी तक कुछ भी करने की फिराक में हो सकते हैं। सुरक्षा चूक से लेकर राजनीतिक उथल–पुथल तक उतार–चढ़ाव भरी यात्रा के बारे में बात करें, तो पंजाब में यह कभी भी सुस्त पल नहीं होता! मुंबई से पुणे तक, महाराष्ट्र में बाबू फेरबदल का खुलासा होता है जैसे ही देश आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, महाराष्ट्र के बाबू गलियारों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक निर्णायक कदम में, राज्य सरकार ने हाल ही में बड़े पैमाने पर बाबू बदलाव को अंजाम देते हुए 12 आईएएस अधिकारियों को नई भूमिकाएँ सौंपी हैं। उनमें से उल्लेखनीय है 1988–बैच के वरिष्ठ अधिकारी राजेश कुमार का सहयोग



और विपणन के अतिरिक्त मुख्य सचिव से राजस्व के अतिरिक्त मुख्य सचिव के महत्वपूर्ण पद पर स्थानांतरण। इस बीच, ओ.पी. गुप्ता ने नितिन करीर के मुख्य सचिव बनने के बाद छोड़ी गई रिक्ति को भरते हुए, वित्त की देखरेख की भूमिका में कदम रखा। संजय सेठी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल से लौटते हुए, परिवहन के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में बागडोर संभालते हैं, पराग जैन नैनुटिया को विस्थापित करते हुए, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में चले गए हैं। फिर विजय सिंघल हैं, जो अब सिडको में जहाज का संचालन कर रहे हैं और मिलिंद शंभरकर मुंबई मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड में कार्यभार संभाल रहे हैं। यह फेरबदल मुंबई से आगे तक फैला है, जिसमें कविता द्विवेदी को अकोला नगर निगम के आयुक्त से पुणे डिवीजन के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है। इन बदलावों के बीच, यह देखते हुए कि शीर्ष पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार की काफी भीड़ है, हर कोई यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस फेरबदल के पीछे कौन है।

# पर्यावरण संतुलन के लिये वन्यजीवों की रक्षा जरूरी

ललित

अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करने में डूबे इंसान को अब यह अंदाजा ही नहीं रह गया है कि वह अपने साथ–साथ लाखों वन्य जीवों के लिए इस धरती पर रहना कितना दूभर कर दिया है। तथाकथित विकास एवं स्वार्थ के नाम पर धरती पर मौजूद संसाधनों का प्रबंधन और दोहन इस तरह से किया जा रहा है कि वन्य जीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा हैं। कितने ही पशु–पक्षियों की प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, तो कितनी विलुप्ती कगार पर हैं। दुनियाभर में तेजी से विलुप्त हो रहे वन्य पेड़–पौधों और जीव–जंतुओं के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं वन्यजीवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी आदि अन्य खतरों पर नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जंगली वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के फायदे बताकर जागरुक किया जाता है और वन्यजीव अपराध और वनों की कटाई के कारण वनस्पतियों और जीवों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आह्वान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को, अपने 68वें अधिवेशन में वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरुक करने एवं वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। महासभा ने वन्यजीवों के पारिस्थितिकी, आनुवांशिकी, वैज्ञानिक, सौंदर्य सहित विभिन्न प्रकार से अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा देने को प्रेरित किया। विभिन्न जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों के अस्तित्व की रक्षा ही इसका उद्देश्य कहा जा सकता है। इस दिवस की शुरुआत थाईलैंड में हुई थी। विश्व वन्यजीव दिवस मनाये जाने का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों से हमें भोजन तथा औषधियों के अलावा और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इनमें से एक है वन्यजीव जलवायु संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। वन्यजीव मानसून को नियमित रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों की पुनःप्राप्ति में सहयोग करते हैं। पर्यावरण में जीव–जंतु तथा पेड़–पौधों के योगदान को पहचानकर तथा धरती पर जीवन के लिए वन्यजीवों के अस्तित्व का महत्व समझते हुए हर साल विश्व वन्यजीव दिवस अथवा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। वन्य जीवों के सामने तस्करी के अलावा अन्य अनेक खतरे हैं। अब इन वन्य जीवों में 'फॉरएवर केमिकल्स' पाये जाने से इनका जीवन लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों को ध्रुवीय भालू से लेकर बाघ, बंदर और डॉलफिन जैसी मछलियों की 330 वन्यजीव प्रजातियों में 'फॉरएवर केमिकल्स' के पाए जाने के सबूत मिले हैं। जो दर्शाते हैं कि इंसानों द्वारा बनाया यह केमिकल न केवल पर्यावरण बल्कि उसमें रहने वाले अनगिनत जीवों के शरीर में पहुंच चुका है और उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इनमें से कई प्रजातियां पहले ही खतरे में हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में मछलियों और अन्य जलीय जीवों में यह फॉरएवर केमिकल मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक चूंकि यह केमिकल्स आसानी से नष्ट नहीं होते ऐसे में यह लम्बे समय तक वातावरण में मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं यह वातावरण के माध्यम से लंबी दूरी तक भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के सुदूर क्षेत्रों में जो जहां जीव अभी भी औद्योगिक स्रोतों से दूर है जैसे अंटार्कटिका में पेंगुइन या आर्कटिक में ध्रुवीय भालू भी इन हानिकारक केमिकल्स के चपेट में आ सकते हैं। अन्य शोधों से पता चला है कि इन हानिकारक केमिकल्स के संपर्क में आने से वन्यजीवों को भी इसी तरह नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह संभावित स्वास्थ्य समस्याएं लुप्तप्राय या संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने अस्तित्व के लिए अन्य खतरों के साथ–साथ इन हानिकारक रसायनों से भी जूझना पड़ रहा है। 'फॉरएवर केमिकल्स' की ही भांति वन्यजीवों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी के कारण भी वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ सालों में तस्करों के अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क एवं गिरोहों के कारण वन्यजीवों की तस्करी बढ़ी है। लम्बे समय से यह जरूरत महसूस की जा रही है कि वन्यजीव और इनके अंगों के तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने का काम तेजी से होना चाहिए। लेकिन, यह काम आगे नहीं बढ़ पाया। वन्यजीवों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी को रोकने के लिए भारत समेत पांच देशों की सामूहिक रणनीति से काम करने की पहल को सकारात्मक ही कहा जाएगा। तस्करी के कारण जिन देशों में वन्यजीव खतरे में नजर आते हैं, वहां समन्वय की कमी भी एक कारण माना जाता है। इसकी वजह से यह गैरकानूनी काम बेरोकटोक होता रहा है। आमतौर पर तस्करी के जरिए दूसरे देश से ऐसे वन्यजीव लाए जाते हैं, जो स्थानीय जंगल में नहीं मिलते। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के विशेषज्ञों के साथ मिलकर दो दिन तक इस संकट पर गहन मंथन भी किया है। इन देशों ने वन्यजीवों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। यह तंत्र इन देशों में वन्यजीवों की बरामदगी के प्रकरणों का विश्लेषण करेगा। साथ ही तस्करों के नेटवर्क की पहचान कर इसे इंटरपोल की मदद से तस्करों के वित्तीय प्रवाह के तंत्र को तोड़ने का काम भी करेगा। यह सर्वविदित बात है कि वन्यजीवों की तस्करी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जिसके ज्यादातर उन देशों में अपने संपर्क हैं, जिनके सहयोग से संरक्षित श्रेणी के वन्यजीवों की तस्करी एक देश से दूसरे देश में की जाती है। जहां इन वन्यजीवों की मांग होती है, उन देशों से ये तस्कर मोटी कमाई भी करते हैं। यह तथ्य भी सामने आया कि इन दिनों वन्यजीवों की तस्करी के लिए वायु मार्ग प्रमुख माध्यम बन गया है। इन जीवों को अफ्रीकी देशों से दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों में लाया जा रहा है।

# घरेलू हिंसा में पुरुष प्रताड़ना क्यों?

विनोद

डा. वरिंद्र भाटियामीडिया द्वारा उपलब्ध अनेक पुख्ता और ताजा रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत भी पुरुषों के ऊपर घरेलू हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कठोर कानून भी बने हैं, लेकिन पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। रिसर्च पर आधारित तथ्य बताते हैं कि देश में घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों में करीब चालीस फीसदी शिकायतें पुरुषों से संबंधित होती हैं, यानी इनमें पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं और उत्पीड़न करने वाली कुछ महिलाएं होती हैं। भारत में अभी तक ऐसा कोई सरकारी अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिससे इस बात का पता लग सके कि घरेलू हिंसा में शिकार पुरुषों की तादाद कितनी है, लेकिन कुछ गैर सरकारी संस्थान इस दिशा में जरूर काम कर रहे हैं। 'सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन' और 'माई नेशन' नाम की गैर सरकारी संस्थाओं के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारत में नब्बे फीसदी से ज्यादा पति तीन साल की रिलेशनशिप में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का सामना कर चुके होते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुरुषों ने जब इस तरह की शिकायतें पुलिस में या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर करनी चाही तो लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और शिकायत करने वाले पुरुषों को हंसी का पात्र बना दिया गया। कुछेक महिलाओं द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित करने से, पुरुषों द्वारा आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। इसके पीछे तमाम कारणों में पुरुषों का घरेलू हिंसा का शिकार होना भी बताया जाता है जिसकी शिकायत पुरुष किसी फोरम पर कर भी नहीं पाते हैं। उनमें सबसे बड़ा तर्क यह है कि महिलाओं को सुरक्षा देने के जो कानून बने हैं, उनके दुरुपयोग से पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। मौजूदा कानून धारा 498–ए, अमरीका के जिस कानून से प्रेरित होकर यह कानून बनाया गया था, वह अमरीकी कानून जेंडर निरपेक्ष है और उसमें पुरुषों की प्रताड़ना के मामले भी देखे जाते हैं। रेप से जुड़े सख्त कानून हों या महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बना कठोर कानून का यही मकसद है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लग सके, जो ठीक ही है, परंतु अब कई जगह इन कानूनों का तथाकथित दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। यहां तक कि कुछ मामलों में देखा गया है कि फर्जी मामलों के जरिए ब्लैकमेल कर उगाही की कोशिश भी की जाती है। जैसे कि ब्रेकअप हो गया तो पार्टनर ने रेप का केस कर दिया। लंबे समय तक लिव–इन में रहे, लेकिन अनबन हो गई तो रेप का केस कर दिया, पति से अनबन हो गई, बात ज्यादा बिगड़ गई तो उसे घरेलू हिंसा के झूठे केस में फंसा दिया, इत्यादि। इस समय ऐसे मामलों में काफी वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या इन घटनाओं के कारण झूठे है'या नहीं, इसका जवाब तो आत्म दर्शन से भी आसानी से मिल सकता है। महिलाओं द्वारा पुरुषों पर हिंसा आज एक आम समस्या बन गई है। इसमें आर्थिक, शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार भी शामिल है, जो किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। पुरुष और महिलाएं भी लिंग आधारित हिंसा के शिकार हैं। भारत जैसे देश में, जो सदियों से पुरुष–प्रधान रहा है, लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि पुरुष भी महिलाओं की तरह घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि भारत में किसी भी कानून में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि, आम धारणा के विपरीत, महिलाओं द्वारा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने वाले पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। देश में मौजूदा कानूनों को देखते हुए, ऐसा कोई खास कानून नहीं है जो पुरुषों को अंतरंग साथी की हिंसा से बचाता हो। हां, कानून के अलावा, कुछ अन्य कारण भी मौजूद हैं जिनके कारण ऐसे मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं, इनमें से एक है — सामाजिक धारणा कि पुरुष मजबूत होते हैं और रोना मुश्किल होता है, या यदि उन्हें कानूनी सहायता मिलती है।

# भारत में अत्यधिक गरीबी आती है, लेकिन अत्यधिक असमानता नहीं

संजय

हर किसी को सर्वेक्षण पसंद आता है, खासकर विरोधाभास से ग्रस्त देश में। उस सर्वेक्षण को लीजिए जो चर्चा में बना हुआ है और जैसे–जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तेजी से प्रभावशाली प्रचार सामग्री के रूप में उभर रहा है। 11 साल के अंतराल के बाद, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने देश में घरेलू उपभोग व्यय पर डेटा जारी किया है। यह प्रारंभिक तथ्य पत्र है, अभी विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। लेकिन तेजी से ध्रुवीकृत परिदृश्य में, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके विरोधी दोनों ही अपने–अपने राजनीतिक आख्यान बेचने के लिए इस पर कूद पड़े हैं। प्रस्ताव पर भारत की नाटकीय रूप से भिन्न छवियां हैं। अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान आयोजित घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) से निकलने वाली ष्अच्छी खबरष् और सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा चिह्नित, गरीबी में नाटकीय कमी के बारे में है, 2022 में प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च दोगुने से अधिक होने के बाद से है। 2011–12 की तुलना में 23, उन भारतीयों के बारे में जो बेहतर खा रहे हैं और जिनकी खर्च करने योग्य आय अधिक है। इनमें से कुछ दावों को पुष्ट करने के लिए डेटा मौजूद है – भारतीय वास्तव में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के प्रतिशत के रूप में भोजन पर कम और कपड़े, प्रसाधन सामग्री, टिकाऊ सामान आदि पर अधिक खर्च कर रहे हैं। वे सूखे फल पर अधिक खर्च कर रहे हैं। – 2011–2012 में एमपीसीई के 0.58 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 1.15 प्रतिशत हो गया। ये सब भारत की कहानी का हिस्सा है. लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि अगर देश में सब कुछ इतना ष्चमकदारष् है, तो ग्रामीण भारत के सबसे गरीब पांच प्रतिशत – लगभग सात करोड़ लोग – प्रति दिन केवल 46 रुपये क्यों खर्च करते हैं। चुनाव की पूर्व संध्या पर जारी एक सर्वेक्षण एक राजनीतिक उपकरण बन जाता है, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन नागरिक का दृष्टिकोण भी है। एक बुनियादी सवाल सामने आता हैरू क्या भारत सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है? यहाँ, चित्र मिश्रित है। स्पष्ट रूप से, देश के विशाल हिस्से में अत्यधिक गरीबी कम हो रही है। लेकिन अत्यधिक असमानता नहीं है. अत्यधिक असमानता मायने रखती है क्योंकि यह देश को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के रास्ते में आती है। नवीनतम घरेलू सर्वेक्षण सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच, राज्यों के बीच, शहरों और गांवों के बीच और सामाजिक समूहों के बीच अंतर के बारे में कुछ ठोस तथ्य पेश करता है। भारत की ग्रामीण आबादी के निचले पांच प्रतिशत का औसत एमपीसीई केवल 1,441 रुपये हैय शहरी क्षेत्रों में यह 2,087 रुपये हैय भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष पांच प्रतिशत का औसत एमपीसीई क्रमशः 10,581 रुपये और 20,846 रुपये है। राज्यों में, सिक्किम में एमपीसीई सबसे अधिक है (ग्रामीण – 7,787 रुपये और शहरी – 12,125 रुपये)य रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम (ग्रामीण – 2,575 रुपये, शहरी – 4,557 रुपये) है। नवीनतम एचसीईएस डेटा सामाजिक समूहों के बीच तीव्र दरार को भी दर्शाता है। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों दूसरों से पीछे चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे कम एमपीसीई 3,098 रुपये थी, इसके बाद अनुसूचित जातियों के लिए 3,571 रुपये थी। भोजन पर घरेलू खर्च के बदलते पैटर्न को देखना दिलचस्प है। भोजन पर कुल व्यय में अनाज और दालों की हिस्सेदारी गांवों और शहरों दोनों में तेजी से कम हो रही है। अनाज पर खर्च किया गया एमपीसीई हिस्सा 2011–12 में 10.7 प्रतिशत से गिरकर 2022–23 में 4.9 प्रतिशत हो गया। इसका एक कारण सरकार की मुफ्त खाद्यान्न योजनाओं को माना जा सकता है। यह भी सच है कि प्रोटीन युक्त डेयरी उत्पाद, अंडे, मछली, मांस और ताजे फलों का अधिक सेवन किया जा रहा है। जैसा कि कहा गया है, ऐसे प्रश्न हैं, परेशान करने वाले निष्कर्ष हैं, और बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि भारतीय बेहतर भोजन की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या हम अल्ट्रा–प्रोसेस्ड भोजन की खपत में तेज वृद्धि को ध्यान में रख रहे हैं? एचसीईएस 2022–2023 से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारतीय अधिक मात्रा में पेय पदार्थ और अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन का सेवन कर रहे हैं जो अस्वास्थ्यकर हैं। ष्पेय पदार्थ, प्रसंस्कृत भोजन और अन्यष् पर व्यय का हिस्सा 2011–12 में कुल एमपीसीई के 7.9 प्रतिशत से बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गया है। इसके साथ ही, इसी अवधि में ष्पान (सुपारी), तम्बाकू और नशीले पदार्थोंष् पर खर्च 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया है। यह वयस्कों और बच्चों में बढ़ते मोटापे और देश में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में चिंताजनक वृद्धि की पृष्ठभूमि में हो रहा है। नवीनतम घरेलू उपभोग सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा उपचार (अस्पताल में भर्ती और गैर–अस्पताल में भर्ती दोनों) पर बढ़ते खर्च को दर्शाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैरू लिंग। फैक्ट शीट हमें अंतर–घरेलू भोजन की खपत या संसाधनों के आवंटन के बारे में कुछ नहीं बताती है। कौन क्या, कब और कितना खा रहा है, इस पर हमें अधिक विस्तृत डेटा की आवश्यकता है ताकि हम निर्णायक रूप से यह कह सकें कि सभी भारतीयों के लिए आहार में सुधार हुआ है या नहीं। परिवहन संबंधी आंकड़ों के साथ भी यही स्थिति है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही भारतीय परिवहन पर अधिक खर्च कर रहे हैं। कुल मिलाकर, परिवहन पर खर्च 2011–12 में एमपीसीई के 4.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में एमपीसीई के 7.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। प्रश्नरू क्या व्यय में यह तीव्र वृद्धि अधिक गतिशीलता के बारे में है या इसके बारे में ईंधन की लागत में वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति? इसके अलावा, क्या परिवहन पर खर्च किया जाने वाला अतिरिक्त पैसा महिलाओं और पुरुषों के लिए आवाजाही की अधिक स्वतंत्रता और अवसरों की ओर ले जाता है? सबसे हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हमें बताता है कि 15–49 आयु वर्ग की केवल 42 प्रतिशत महिलाओं ने आंदोलन की स्वतंत्रता का आनंद लेने की सूचना दी है। इसका मतलब है कि बाजार, स्वास्थ्य सुविधा और गांव या समुदाय के बाहर के स्थानों पर अकेले जाने में सक्षम होना। यह 41 प्रतिशत (एनएफएचएस–4, 2015–16) से बहुत मामूली वृद्धि दर्शाता है। और भी चिंताजनक बातें हैं।

# 34 लाख 21 हजार की लागत से बनेगी सीसी रोड

सुल्तानपुर। इसौली विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने अपनी विधान सभा क्षेत्र के डड़वा मजरे सादुल्लापुर गांव में 34 लाख 21 हजार रुपये से बनने वाली सीसी सड़क का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इसौली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत को लेकर लगातार सुधार का क्रम जारी है। गुरुवार को विधायक ने त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत विकास खंड बल्दीराय के डड़वा सादुल्लापुर गांव में प्रदीप कुमार यादव के घर के पास से प्राथमिक विद्यालय छतौना डड़वा होते हुए शिवलाल रैदास के घर तक सीसी रोड़ निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने लोगों से कहा कि सड़क के माध्यम से गांव व कस्बों में विकास पहुंच रहा है। क्षेत्र को विकसित करना है। इसके लिए जरूरी है कि सड़क का निर्माण हो।इस दौरान मौजूद रहे अधिकारियों व कर्मचारियों से विधायक ने कहा कि वह सड़क निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। कहीं पर कोई दोषी मिला तो कार्रवाई तय है। इस मौके पर इसौली विधानसभा अध्यक्ष स्वामी नाथ यादव,पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश कनौजिया,उमाकांत यादव, ब्लाक अध्यक्ष बृजेश यादव,जेई जितेंद्र मोहन शर्मा,साबिर अली,प्रधान कमाल खान, पूर्व प्रधान प्रदीप कुमार यादव, पूर्व प्रधान मोहम्मद सरवर,बीडीसी तनवीर आलम,जगन्नाथ यादव,हरि शंकर पाठक,श्रीराम वर्मा,देवी प्रसाद वर्मा,ह्रदय राम यादव,बद्रीनाथ यादव, राम नारायण यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

# दीवाल गिरने से दबकर वृद्ध की मौत

सुलतानपुर। हलियापुर थाना क्षेत्र के नेवादा निवासी फारुक अहमद (61) पुत्र खालिद अहमद अपनी भैंस बांधने के लिए अपनी ही कच्चे घर की दीवाल के बगल खूंटा गाड़ रहे थे कि अचानक भरभराकर दीवाल गिर गई। जिसके नीचे आने से उनकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर लेखपाल ओम प्रकाश पहुंचे व सूचना उच्चाधिकारियों को भेजी है।

# डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर

## 10000 करोड़ की लागत से 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जनपद एवं आस पास के क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्यों का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा बी0आर0पी0 इंटर कालेज मैदान में मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री गिरीश चंद्र यादव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) परिवहन विभाग उ0प्र0 श्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी, एमएलसी बृजेश सिंह (प्रिंसू), विधायक बदलापुर श्री रमेश चंद्र मिश्रा, शाहगंज विधायक श्री रमेश सिंह, विधायक मड़ियाहूँ डा0 आर. के. पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्य ,जिलाध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर लगभग रु. 10000 करोड़ की लागत से 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। रू. 1895 करोड़ की लागत से 28 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग–135 ए गोमती नदी पर पुल सहित एन.एच.–31 के टोल प्लाजा से पूर्वांचल विश्वविद्यालय तक जौनपुर शहर के पूर्व दिशा में बाईपास का निर्माण, रू. 1512 करोड़ की लागत से 31 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए खेतासराय–शाहगंज ग्रीनफील्ड बाईपास सहित पूर्वांचल विश्वविद्यालय से शाहगंज तक 4 लेन निर्माण, रू. 1653 करोड़ की लागत से 45 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए शाहगंज–कलान–मालीपुर– अकबरपुर खण्ड का 4 लेन चौड़ीकरण एवं अकबरपुर बाईपास का निर्माण, रू. 438 करोड़ की लागत से 7 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए मड़ियाहूँ शहर के पश्चिम में नये 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण, रू. 99 करोड़ की लागत से 5 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 128ए जौनपुर शहर में लता मंगेशकर तिराहे से प्रसाद इस्टीट्यूशन तक 4 अण्डरपास सहित 4 लेन निर्माण, रू. 1000 करोड़ की लागत से 19 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जौनपुर–प्रयागराज मार्ग तक जौनपुर शहर के पश्चिम में बाईपास का निर्माण, रू. 1386 करोड़ की लागत से 19 किमी लम्बाई आजमगढ़ बाईपास (पैकेज–4) का निर्माण, रू. 863 करोड़ की लागत से 17 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 319डी प्रयागराज से फूलपुर तक 4 लेन सड़क एवं फूलपुर बाईपास का निर्माण, रू. 1013 करोड़ की लागत से 23 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 319डी मुंगराबादशाहपुर बाईपास सहित फूलपुर–मुंगराबादशाह पुर तक 4–लेन का

निर्माण, रू. 18 करोड़ की लागत से 11 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 319डी फूलपुर–मुंगराबादशाहपुर मौजूदा सड़क खण्ड के रख–रखाव का शिलान्यास मा0 केन्द्रीय मंत्री जी के द्वारा किया गया। इस दौरान मा0 राज्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुरोध पर उन्होंने पालीटेक्निक चौराहे से सिटी स्टेशन रोड पर बने ओवर ब्रिज की ओर सर्विस रोड बनाने एवं मा0 राज्यसभा सांसद के अनुरोध पर मुंगराबादशाहपुर में नगर के अन्दर की सड़को के सुदृढीकरण करने की मांग पर कार्य पूर्ण कराने की घोषणा की।

मा0 कैबिनेट मंत्री जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि उक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त जनपद जौनपुर में आवागमन सुगम हो जायेगी और जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, यातायात में समय की बचत, ईंधन की बचत, उचित सड़क सुरक्षा, वाहनों की परिचालन क्षमता में वृद्धि, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार के अवसर में वृद्धि, शहर में जाम से निजात, क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से किसान, व्यापारी, आमजनमानस सभी को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आज किसान न सिर्फ अन्नदाता है अपितु ऊर्जा दाता बनने की ओर अग्रसर है, आज भारत में चौमुखी विकास हो रहा है, देश में बायो इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था की पंक्ति में शामिल हो।

इस अवसर पर माननीय राज्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री गिरीश चन्द्र यादव जी द्वारा द्वारा कैबिनेट मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी को अंगवस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया।

मा0 राज्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री गिरीश चंद्र यादव जी ने कहा कि इस परियोजना से लोगो को जाम से निजात मिलेगी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी सहित हर क्षेत्र में देश का तेजी से विकास हो रहा है, देश में गुणवत्तापरक सड़कों को निर्माण कराया जा रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से मजबूत हुई ह और देश में आवास, शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त किया जा रहा है। मा0 राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मा0 केन्द्रीय मंत्री जी ने देश को सड़को को बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में गुणवत्तापरक सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। एमएलसी ब्रजेश सिंह (प्रिन्सू), विधायक बदलापुर श्री रमेश चंद्र मिश्रा, विधायक शाहगंज रमेश सिंह ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित राज्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री गिरीश चंद्र यादव, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी, एमएलसी बृजेश सिंह (प्रिंसू), विधायक बदलापुर श्री रमेश चंद्र मिश्रा, शाहगंज विधायक श्री रमेश सिंह, विधायक मड़ियाहूँ डा0 आर.के. पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम, सहित जिलास्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

# खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग,एक अधेड़ की मौत,दो लोग घायल

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) अरवल थाना क्षेत्र के अदनिया गांव में शुक्रवार की दोपहर घर मे खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग जाने से एक अधेड़ की आग से जलकर मौके पर मौत हो गयी। तथा आग बुझाने में दो लोग झुलसकर घायल हो गए।दोनो घायलो को इलाज के लिए सीएचसी हरपालपुर में भर्ती कराया गया जहां से एक की हालत गम्भीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर अरवल थाना क्षेत्र के अदनिया गांव निवासी नन्हे पुत्र बृजलाल के घर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गयी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और आग के आगोश में आने से लगभग 55 वर्षीय गंगाराम पुत्र गिरवर की जलकर मौके पर मौत हो गयी।उधर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे गांव निवासी जितेंद्र (35) पुत्र कल्लू व रवि राजपूत (25) पुत्र छविनाथ राजपूत सहित दो लोग झुलसकर घायल हो गए।घटना की सूचना अग्निशमन को दी गयी लेकिन जब तक अग्निशमन टीम घटनास्थल पहुंची तब तक ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था।उधर घटना की सूचना मिलते ही अरवल थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवार आनन फानन में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंच गए।और उन्होंने दोनो घायलो को इलाज के लिए सीएचसी हरपालपुर में भर्ती कराया जहां से जितेंद्र की गम्भीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक के का शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।एसडीएम डॉक्टर अरुणिमा श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व टीम को मौके पर भेजकर अग्निकांड से हुए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है तथा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्यवाई कर पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी जाएगी।

# साफ करने का झांसा देकर उड़ा दिए पांच लाख के जेवर

कुशीनगर, संवाददाता। सोने और चांदी के जेवर की सफाई का झांसा देकर करीब पांच लाख का जेवर मंगलवार को दो जालसाज लेकर चंपत हो गए। कुछ देर बाद गहना बदलने का शक हुआ तो महिला ने अपने पति को जानकारी दी। घर पहुंचा पति पत्नी को रोता देख परेशान हो गया और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस से सीसी टीवी फुटेज की मदद से जालसाज की तलाश करने में जुटी है। सुकरौली बाजार कस्बा के वार्ड नंबर दो रामजानकी नगर निवासी छोटेलाल शास्त्री की पत्नी घर पर अकेली थी। दोपहर में दो युवक पहुंचे और अपनी बातों में महिला को फंसा लिए। दोनों युवक महिला से जेवर का साफ करने वाला बताया। जेवर की सफाई युवकों के झांसे में आई महिला अपना जेवर लाकर सफाई के लिए दे दिया। सफाई के दौरान जेवर बदलकर जालसाज चले गए। इसके एवज में महिला से कुछ रुपये भी जालसाज लिए। युवकों के जाने के कुछ देर बाद महिला को जेवर बदले जाने की जानकारी हुई। किसी काम से बाजार गए पति को इसकी जानकारी फोन कर दी। पीड़ित के अनुसार सोने की तीन अंगूठी, झाला,गले की चौन समेत करीब पांच लाख रुपये का जेवर लेकर भाग निकले, जिसकी कीमत पांच लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस की जांच में घर के बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों जालसाज जाते हुए दिखे हैं।पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। सीओ कुंदन सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जालसाज सीसी टीवी फुटेज में जाते हुए दिखे हैं।

उचक्कों के पकड़े जाने की सूचना पर लोग पहुंचे पुलिस चौकी

सुकरौली कस्बे में गहने की सफाई के नाम पर पांच लाख के गहने लेकर फरार होने वाले उचक्के को पकड़े जाने और पुलिस को लेकर जाने की सूचना कस्बे में किसी ने फैला दिया। नगर के चेयरमैन राजनेती कश्यप के साथ कई लोग चौकी पर पहुंच गए। इस घटना के बाद कस्बे में अफरा तफरी मची रही।चौकी इंचार्ज संदीप सिंह ने बताया कि एक दूसरे मामले में एक युवक को पुलिस पकड़कर लाई है।

# कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत

मिर्जापुर, संवाददाता। मिर्जापुर सोनभद्र मार्ग पर स्थित करमा पेट्रोल पंप के पास कार की टक्कर से बाइक सवार महिला, पुत्र व पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हो गई। बहू की हालत गंभीर देख ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुत्र का इलाज सीएचसी राजगढ़ में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया।

यह है पूरा मामला

सोनभद्र जनपद के करमा थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव निवासी संतोष कुमार यादव (35) अपनी पत्नी कौशल्या देवी (32) व मां कुमारी देवी (55) को बाइक से लेकर वाराणसी इलाज कराने जा रहा था। जैसे ही करमा पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरवाने के लिए पीछे देखे बिना अचानक मुड़ा, पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई। वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां, पुत्र व पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने वाले वाहन मालिक ने अपने वाहन से ही सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में ले जाकर भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान कुमारी देवी की मौत हो गई।

पति–पत्नी दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती

गंभीर रूप से घायल कौशल्या को बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। घायल संतोष का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में इलाज चल रहा है। सीएचसी के डॉक्टर की सूचना पर पहुंची करमा थाने की पुलिस कार व शव को कब्जे में लेकर कर्मा थाना सोनभद्र गई। पंचनामा कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

सीएचसी पर तैनात अजित केशरवानी ने बताया कि कार की टक्कर से बाइक सवार दो महिला सहित तीन लोग घायल हो गए थे। जिसमें इलाज के दौरान कुमारी देवी की मौत हो गई। दूसरी महिला की हालत नाजुक देख ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। युवक को हल्की चोट लगी थी। उसकी स्थिति सामान्य है।

# मोनिका पाल हत्याकांड, परिजनों से मिले कांग्रेस और सपा के लोग

वाराणसी, संवाददाता। वाराणसी के चर्चित मोनिका पाल हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गुरुवार को दोपहर बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कपसेठी थाना क्षेत्र के भिटकुरी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए मामले की जानकारी ली। साथ ही मामले के जल्द खुलासा के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, अरुण सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, अनुपम पांडेय, राहुल सिंह, सुनील राय आदि। अजय राय ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस तथा विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के लोग परिजनों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पांच मार्च तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं किया गया और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं हुई तो 6 मार्च को धरना–प्रदर्शन किया जाएगा। वाराणसी पुलिस, पीड़ित परिजनों व रिश्तेदारों को परेशान करने की बजाय अपराधियों को पकड़ने में तेजी लाए। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। बनारस में ऐसी घटनाओं की हम घोर निंदा करते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों के साथ इस तरह का घिनौनी घटनाएं हो जा रही हैं। अजय राय ने मृतका के पिता पुनवासी पाल को ढांढस बंधाते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं। जब तक इस मामले में परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे।

समाजवादी पार्टी ने भी की खुलासे की मांग

वहीं, दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव ने भी घटना की जानकारी ली। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए मामले की जल्द खुलासा करने की मांग की है।

पीड़ित परिवार से मिले अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन

चर्चित मोनिका पाल हत्याकांड में अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन आकाश पटेल ने भिटकुरी गांव पहुंचकर मृतिका मोनिका पाल के पिता पुनवासी पाल तथा अन्य परिजनों से मिलकर घटना से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि घटना में शामिल युवक की तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच की भी टीम लगाई गई है। घटना से जुड़े प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है। जल्द ही मामले की खुलासा किया जाएगा।

यह है मामला

बताते चलें कि 19 फरवरी को मोनिका पाल अपने घर से सहेली के यहां से किताब लाने के लिए निकली थी, जो देर रात तक अपने घर नहीं पहुंची। अगली सुबह बनारस स्टेशन पर खड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस के बोगी में शौचालय के पास बोरे में उसकी लाश मिली थी।

# यू पी बोर्ड के सचिव ने किया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण

प्रयागराज, संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। जिले में अभी तक किसी भी केंद्र से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है. अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जिला विद्यालय निरीक्षण पीएन सिंह ने बताया कि हाईस्कूल की विज्ञान की परीक्षा में एक लाख एक हजार 163 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। सचल दल की नौ टीमें लगातार केंद्रों का दौरा कर रही हैं।

# सीएम योगी ने फायर स्टेशन का किया उद्घाटन

मऊ, संवाददाता। मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के चलीसवा गांव में नव निर्मित फायर स्टेशन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ से वर्चुअल उद्घाटन किया। फायर स्टेशन के संचालन से तहसील के 100 गांवों में आग लगने से होने वाले वाले नुकसानों को रोकने में मदद मिलेगी। अभी तक पहले केवल गर्मी के मौसम में ही यहां अस्थायी फायरब्रिगेड जवानों की तैनाती रहती थी, लेकिन अब दो अग्निशमन वाहन, पांच फायर कर्मियों की तैनाती होगी। इससे पहले चार्ज लेने के बाद गुरुवार को जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक इलामारन अपने पहले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर शिलापट्ट से पर्दा हटाया और नए फायर स्टेशन को लोगों की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने कहा कि फायर स्टेशन से क्षेत्र में होने वाली अगलगी की घटनाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कहा कि जिले में अपराध को कम करना और किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय न हो ये उनकी प्राथमिकता होगी।

# गायत्री मंदिर पिहानी परवैवाहिक वर्षगांठ पर केक नहीं, हवन से संस्कृति की महक

## कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारी व समाजसेवी दिनेश लोहिया व इंदु गुप्ता का हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई वैवाहिक वर्षगांठ

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) गायत्री शक्तिपीठ पिहानी के माध्यम से गायत्री परिवार निरंतर जन्मदिवस व वैवाहिक वर्षगांठ हवन पूजन के साथ कर रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह प्रातः काल गायत्री मंदिर पिहानी पर ट्रस्टी मृदुल कपूर ने कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारी व समाजसेवी दिनेश लोहिया व इंदु गुप्ता की वैवाहिक वर्षगांठ यज्ञ में आहुतियां डालकर मनाई। कई परिवार अब ऐसे हैं जो जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ जैसे शुभ अवसरों पर केक काटने की जगह हवन को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके माध्यम से खुशी मनाने के साथ ही नई पीढ़ी संस्कार भी सीख रही है। हवन की वेदी से उठने वाली महक से पवित्रता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान प्रकट हो रहा है। बच्चों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर व्यवस्थापक राजू मिश्रा ,धर्मेंद्र राठौर ,अनिल राठौर , वीरेश गुप्ता ,रमेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता , रामेश्वर शर्मा पंकज वर्मा , नमन, आशीष सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। संकल्प के बहाने संस्कृति से करा रहे परिचित–ट्रस्टी मृदुल कपूर

गायत्री प्रज्ञा पीठ पिहानी के प्रमुख श्री अतुल कपूर के छोटे भाई ट्रस्टी मृदुल कपूर बताते हैं कि वैवाहिक वर्षगांठ व जन्मदिन पर हवन व दीपयज्ञ के दौरान उनको संकल्प भी दिलाते हैं। इसके पीछे भारतीय संस्कृति से परिचय कराना, जुड़ाव लगाव के साथ ही संस्कारवान बनाना है।

# सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर अब नहीं हो सकेगी घटतौली'

## 'सभी दुकानों पर इंस्टॉल होगी इलेक्ट्रानिक तौल मशीन'

अयोध्या (क्राइम रिपोर्टर) संतोष कुमार। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर अब घटतौली नही हो सकेगी। इसके लिए प्रदेश कि योगी सरकार ने जनपद मुख्यालय पर इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन भेजी है। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से थंब इंप्रेशन की डिवाइस को जोड़ दिया जाएगा। तौल मशीन पर सही वजन होने पर ही थंब इंप्रेशन मशीन पर अंगूठा लग सकेगा। घटतौली होने पर थंब इंप्रेशन डिवाइस पर नहीं होगा प्रोसेस। बाट माप विभाग इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन में डिवाइस इंस्टॉल करेगा। जल्द ही जनपद के सभी सरकारी गल्ले की दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक

तौल मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। ब्लूटूथ से मशीन को कनेक्ट किया जाएगा। इस मशीन को संचालित करने के लिए सभी दुकानदारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जनपद के सभी पांचों तहसीलों के 994 दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन इंस्टॉल की जाएंगी। डीएसओ बृजेश कुमार मिश्र ने बताया कि सोहावल में 165 व सदर तहसील के 238 कोटेदारों की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पहुंच चुकी है। बीकापुर के कोटेदारों के यहां ईडब्ल्यूएस मशीन भेजी जा रही है। इसके बाद मिल्कीपुर व रूदौली क्षेत्र के कोटेदारों की दुकानों पर ईडब्ल्यूएस मशीन भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि ई–पास मशीन से जुड़ने के बाद कोटेदार ऐसा नहीँ कर पाएगा कि उपभोक्ता का अंगूठा लगवा ले और खाद्यान्न न दे। अब अंगूठा लगने के बाद खाद्यान्न देने के बाद ही प्रोसेस पूरा होगा। इस से कोटेदार चोरी नहीँ कर पाएगा। हमारा लक्ष्य है कि मार्च माह में होने वाले खाद्यान्न वितरण तक जिले की सभी 994 कोटे की दुकानों तक ईडब्ल्यूएस मशीन क्रियाशील कर ली जाए।

## सचिन तिवारी एशिया पेसिफिक पीस रिसर्च द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस के लिए चयनित



अयोध्या। शहर के प्रतिष्ठित डेंटल सर्जन डॉ अमित तिवारी के छोटे भाई सचिन तिवारी का चयन एशिया पेसिफिक पीस रिसर्च द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस के लिए श्रीलंका में अपने पेपर को प्रस्तुत करने के लिए हुआ है। बताते चलें कि कांफ्रेंस श्रीलंका में 7 से 10 मार्च के बीच आयोजित हो रहा है।

जिसमें सचिन तिवारी अपने रिसर्च पेपर शिपिंग ग्लोबल पावर इंडिया एज ए इमरजिंग प्लेयर इन एशिया पेसिफिक को प्रस्तुत करेंगे। मालूम हो कि चयनित सचिन अभी वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं।उन्होंने अपना ग्रेजुएशन शहर के ही झुनझुनवाला डिग्री कॉलेज से किया है।उन्होंने एशिया पेसिफिक की पिछली कांफ्रेंस 2022 में भारत के मेघालय राज्य की यूएसटीएम यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई थी,सचिन ने उसमें कांफ्रेंस में भी भाग लिया था।

# '2275 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है समर्थन मूल्य'

## 'पूरे प्रदेश में 15 जून तक चलेगी गेहूं की खरीद, इस वर्ष बटाईदार किसान भी पंजीकरण कराते हुए कर सकेंगे बिक्री'

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो) सुरेंद्र कुमार। पहली मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ होगी, जो 15 जून तक चलेगी। सरकार ने 2275 रुपये प्रति कुंतल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने चाहिए। गेहूं की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल बि.नच.हवअ. पद पर विभाग के मोबाइल ऐप न्च ज्ञ्ैभ।छ डप्ज्त। पर पंजीकरण–नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। विभाग की ओर से किसानों से अनुरोध किया गया है कि गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफकर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर जाएं। इस वर्ष बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की 2275 रुपये प्रति कुंतल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने चाहिए। गेहूं की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल बि.नच.हवअ. पद पर विभाग के मोबाइल ऐप न्च ज्ञ्ैभ।छ डप्ज्त। पर पंजीकरण–नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। विभाग की ओर से किसानों से अनुरोध किया गया है कि गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफकर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर जाएं। इस वर्ष बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। गेहूं खरीद के लिये किसानों का खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल बि .हवअ पद पर पहली जनवरी 2024 से ऑनलाइन पंजीयन शुरू है। अब तक 109709 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर 15 जून तक क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन गेहूं खरीद सुबह 9 से शाम छह बजे तक चलेगी। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग ने इसकी तैयारी भी कर ली गई है। किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों के कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित करने की योजना है। खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है। पहली मार्च से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए विभाग ने सारी तैयारी कर ली है। है। किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों के कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित करने की योजना है। खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है। पहली मार्च से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए विभाग ने सारी तैयारी कर ली है।

'हाइवे पर लूट करने वाले गैंग के तीन अन्तर्राज्जीय लूटेरे गिरफ्तार'

अयोध्या (क्राइम रिपोर्टर) संतोष कुमार।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या द्वारा सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान दिनांक 20.02.2024 थाना



रौनाही क्षेत्र मे हाईवे पर गुटखा एवं जर्दा से लदी डीसीएम गाड़ी से लूट की घटना दर्ज की गयी थी जिसके क्रम में थाना स्थानीय पर जिसके अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद स्तर पर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु तीन टीमे गठित की गयी थी, जिसमे थाना रौनाही की दो टीमे एवं ैव्ळ अयोध्या टीम को निर्देशित किया गया था । अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद अयोध्या के मार्गदर्शन व सहायक पुलिस अधीक्षकध् क्षेत्राधिकारी सदर जनपद अयोध्या के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना रौनाही जनपद अयोध्या के कुशल नेतृत्व में उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर घटना का सफल अनावरण करते हुये वांछित अभियुक्त गण को बहद ग्राम टिकरिया अयोध्या बस्ती हाइवे मार्ग से समय 11.30 बजे गिरफ्तार कर मुकदमा से सम्बन्धित माल शत् प्रतिशत बरामद की गयी। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति बिहार के व्यापारी है जो चोरी ध् लूट के माल की खरीद फरोक्त करते थे । अभियुक्त गण से बरामद माल गुटखाध्जर्दा शिखर पान मसाला की कीमत लगभग 08 लाख रुपये है।

# बहू पर बुरी नजर रखने वाले ससुर सहित परिवार के सात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज

अयोध्या (क्राइम रिपोर्टर) संतोष कुमार। शादी के बाद ससुराल विदा होकर आने के बाद से ही अपनी बहू पर कलियुगी ससुर की गंदी नियत हो गई। बहू के साथ अश्लील हरकत करने लगा। रात में बहू के कमरे में घुसकर अपने कपड़े निकाल कर ससुर बैजनाथ जबरदस्ती अश्लील हरकत व छेड़ छाड़ करने लगा। बहू ने ससुर के अश्लील कृत्य का वीडियो बना लिया। इसका पता ससुराल वालो को लगने के बाद सास ससुर व ननद द्वारा मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। खबर लगने पर उसके पिता आए और उसे घर लेकर चले गए। ससुराल वालो से पीड़ित बहू ने थाना पूरा कलंदर में पति राहुल ससुर बैजनाथ बड़े ससुर गोरख नाथ सास राजकुमारी ननद सिंपल जेठ संतोष व जेठानी रेनू पाण्डेय के विरुद्ध केस दर्ज करने के लिए तहरीर दिया।इसके बाद जांच उपरांत के बाद ससुर बैज नाथ सहित परिवार के सात लोगों के विरुद्ध गंभीर अपराधों में मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज मुकदमा की विवेचना एसआई संतोष कुमार सिंह ने शुरू कर दिया। पीड़िता के अधिवक्ता कमलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि अयोध्या जनपद के थाना महाराजगंज के एक गांव निवासी की पुत्री का विवाह पूरा कलंदर अंतर्गत मोहतसिम पुर निवासी बैजनाथ पाण्डेय के पुत्र राहुल कुमार पाण्डेय से वर्ष 2021 में हुआ था। विवाह के बाद मिले दान दहेज से पति राहुल ससुर बैजनाथ सास राजकुमारी ननद सिंपल संतोष पाण्डेय व उनकी पत्नी रेनू तथा बड़े ससुर गोरखनाथ संतुष्ट न होने के कारण उसका उत्पीड़न किया। पति राहुल संतोष पांडे के साथ अंगूरी बाग में रहने लगा। बैजनाथ ने पीड़िता के साथ उसके कमरे व बाथरूम में कई बार उसके साथ अश्लील हरकत किया। पीड़िता ने अपनी पति राहुल से शिकायत किया तो उसने कहा कि पिता को खुश रखो। मजबूर पीड़िता की तहरीर पर थाना पूरा कलंदर में छेड़खानी व दहेज सहित कई गंभीर अपराध की धाराओं में मा पंजीकृत हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद से विपक्षी उसके परिवार वालों को धमकी देने लगे जिसकी शिकायत उसने एसएसपी अयोध्या से किया। पीड़िता ने महिला आयोग की अध्यक्ष , मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश के उच्च अधिकारियों सहित पुलिस महा निरीक्षक अयोध्या को शिकायती पत्र भेज कर निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग किया है।

# एसपी सिटी ने किया कैंट थाने का निरीक्षण

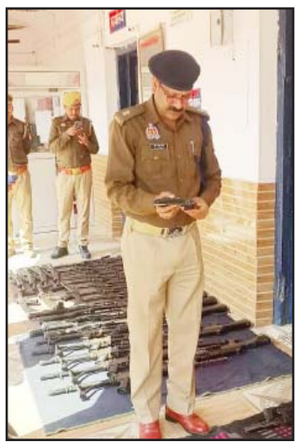



अयोध्या। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या श्री राजकरन नय्यर के निर्देश पर जिले के सभी थानों में संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जहां एक ओर सीओ लाइन ने पुलिस लाइन के कार्यालयों व सभी अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया था। वही उसी कड़ी में आज शुक्रवार को एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने थाना कैन्ट का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया।इस मौके पर उन्होंने थाने के अभिलेखों, कार्यालय, भोजनालय, बैरिक, महिला हेल्प डेस्क, कारागार, शस्त्रागार आदि का निरीक्षण बारीकी से किया। वही अभिलेखों के रख–रखाव व साफ–सफाई के संबन्ध में कुछ कमियां भी मिली जिसे दूर करने के लिये थानाध्यक्ष कैंट को आवश्यक निर्देश दिए।

# एएससीआई और वॉश ने फील्ड में किया सुएज श्रमिकों का सुरक्षा सर्वेक्षण

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी



विकास विभाग के साथ मिलकर गुरुवार को सुएज सफाई कर्मियों के लिए एक बड़ा सुरक्षा सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का मकसद यह जानना था कि सुएज सुविधाओं में काम करने वाले कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। गुरुवार को, एएससीआई की एक टीम ने इंदिरा नगर के सी ब्लॉक स्थित जल कल वाटर टैंक परिसर में स्थित सुएज के जोन 7 कार्यालय का दौरा किया। टीम ने 30 से अधिक सीवर सफाई कर्मचारियों से बातचीत की और उनसे सुरक्षा प्रोटोकॉल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) के उपयोग और समग्र सुरक्षा प्रथाओं को लेकर उनके अनुभवों के विषय में जानकारी प्राप्त की। सर्वेक्षण में श्रमिको ने सुएज सुरक्षा टीम द्वारा दिए गए सुरक्षा प्रशिक्षण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कई सदस्यों ने कहा कि इस प्रशिक्षण ने उनके काम का माहौल बेहतर बनाया है और उनकी सुरक्षा में वृद्धि की है। उन्होंने दस्ताने, चश्मे, हैंड ग्रैबर, रिफलेक्टिव जैकेट, हेलमेट और सुरक्षा जूते जैसे पीपीई किट के महत्व पर भी जोर दिया। सर्वेक्षण के दौरान, श्रमिकों ने सुएज सुरक्षा टीम द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा प्रशिक्षण के प्रभाव के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। कई लोगों ने अपने काम के माहौल को बेहतर बनाने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में दस्ताने, काले चश्मे, हाथ पकड़ने वाले, परावर्तक जैकेट, हेलमेट, सुरक्षा जूते सहित पीपीई किट के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, एएससीआई टीम ने भरवारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का दौरा किया और 100 से अधिक श्रमिकों के साथ उनके काम के दौरान लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं को समझने के लिए बातचीत की। एएससीआई फैकल्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली डॉ. स्नेहलता ने बताया, ष्यह देखना बेहद सुखद है कि सुएज जैसा अंतराष्ट्रीय संगठन दुनिया भर से बेहतरीन सुरक्षा प्रथाओं को लागू कर रहा है। संगठन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों से श्रमिक भी खुश है। यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि न केवल उन्होंने सुरक्षा उपकरणों को सहजता से उपलब्ध कराया है, बल्कि वे अपने कर्मचारियों को उन्हें इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित भी करते हैं। सुएज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राजेश मठपाल ने सुरक्षा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, सुएज का सुरक्षा मंत्र यह है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने सहकर्मी, अपने भाई और अपने समुदाय का रक्षक है। इसका अर्थ है कि हम सब मिलकर एक–दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। हम साइट पर जीवन रक्षक नियम लागू करते हैं। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम सब सुरक्षित रहें। एएससीआई और वॉश द्वारा किया गया सुरक्षा सर्वेक्षण सुएज के अपने कार्यबल की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने के प्रति अटूट समर्पण को रेखांकित करता है। निरंतर प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सुएज सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के अपने मिशन में दृढ़ प्रतिबद्ध है।

# स्टाफ यूनियन उत्तर प्रदेश क्षेत्र ने हाल में ही चल रहे मुद्दों पर की चर्चा



ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। नई भर्ती हुए कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत किया, और आंचलिक स्तर के सदस्यों को समर्थन दिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष राहुल जायसवाल और क्षेत्रीय सचिव मनीष चौहान के नेतृत्व में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय के इकाई समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया। कामगारों को प्रभावित करने वाली मुद्दे जैसे कि कार्यस्थल की स्थिति, कर्मचारी लाभ, और संचार प्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई, जिन पर सही समाधान निकालने की योजना बनाई गई। साथ ही, नए कर्मचारियों का स्वागत किया गया। क्षेत्रीय स्तर के सदस्यों राहुल कनोजिया, अंशिका कौशल और भारती यादव को आंचलिक समिति में सम्मिलित होने पर सम्मानित किया गया।

# 'गैंगेस्टर एक्ट के फरार नफर वारंटियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार'




'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देश में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शाहाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना पाली पुलिस ने गुरुवार अपराह्न को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 10–10 हजार रुपये पुरस्कार घोषित 02 वांछित नफर वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों का पुलिस ने चालान कर दिया। पाली पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के फरार वारंटी फुरकान (22) पुत्र सादिर अली निवासी मोहल्ला आबिदनगर कस्बा व थाना पाली, नाजिर अली उर्फ राजा (26) पुत्र छोटे निवासी मोहल्ला काजी सराय कस्बा व थाना पाली को सोल्जर बोर्ड चौराहा शहर कोतवाली जनपद हरदोई से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही कर दोनों ईनामी नफर वारंटियों को न्यायालय में पेश किया। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने बताया कि कस्बा पाली निवासी फुरकान व नाजिर उर्फ राजा को अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाये जाने गैंगेस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया था। ये दोनों ईनामी वारंटी काफी समय से फरार चल रहे थे। न्यायालय से वारंट जारी होने पर गुरुवार को अपराह्न में पाली पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दोनों नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय,उपनिरीक्षक शिवशंकर मिश्रा,हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल दिलीप कुमार,कांस्टेबल राकेश प्रताप सिंह,कांस्टेबल विनय कुमार, कांस्टेबल जयपाल,कांस्टेबल सुलभ कुमार, महिला कांस्टेबल विजया शर्मा मौजूद रहे।

# एलपीसीपीएस में हुआ जॉब फेस्ट 2024 का आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ने युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जॉब फेस्टिवल का आयोजन किया। इस फेस्टिवल का आयोजन कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल द्वारा किया जाता है। संस्थान के संस्थापक महाप्रबंधक एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉ एसपी सिंह, माध्यम स्टाफिंग सैल्यूशन के प्रमुख सीए राज अग्रवाल, डीन डॉ एल एस अवस्थी एवं विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों और इंडस्ट्री के बीच की खाई को पाटना और युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है।




इस आयोजन में 50 से अधिक कंपनियों की भागीदारी ने एक शानदार सफलता की नींव रखी, जिसमें प्रतिभागियों को विभिन्न नौकरी की पेशकश की गई थी। कंपनियों में आदित्य बिड़ला, एक्सिस बैंक, महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एचसीएल, मिस्टर ब्राउन द्वारा डैनब्रो, और कई अन्य शामिल रहीं।

प्रतिभागियों को कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और अपना बायोडाटा जमा करने का अवसर दिया गया। कंपनियों ने साक्षात्कार आयोजित किए और आगे के दौर के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। इस कार्यक्रम में लखनऊ और उसके आसपास के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। कंपनियां प्रतिभागियों की गुणवत्ता से प्रभावित हुईं और उन्हें विभिन्न नौकरियों की पेशकश की।

पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय नौकरी महोत्सव एक बड़ी सफलता रही है। इस उत्सव में भर्ती करने वालों और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस वर्ष लगभग 1287 अभ्यर्थियों ने इस जॉब फेस्ट में पंजीकरण कराया और 687 योग्य उम्मीदवारों का चयन विभिन्न कंपनियों में हुआ।

## 'अग्निशमन केंद्र आवासीय भवन का हुआ भव्य लोकार्पण'

## 'सवायजपुर के लिये तोहपे से कम नहीं अग्निशमन केंद्र–माधवेन्द्र प्रताप सिंह'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' तहसील सवायजपुर में अग्निशमन केंद्र का प्रशासनिक भवन और आवासीय भवन बनकर तैयार हो गया है।



जिसका लोकार्पण कार्यक्रम गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअली किया। अग्निशमन केंद्र का स्थलीय लोकार्पण सवायजपुर विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह शरानूश की गरिमामयी उपस्थिति में फीता काटकर कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। विधायक ने कहा कि तहसील सवायजपुर क्षेत्र में लोगों को अब आग लगने पर हरदोई मुख्यालय का मुँह ताकना नहीं होगा। अब सवायजपुर से ही तत्काल दमकल की मदद मिल जायेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी, उपजिलाधिकारी डॉ अरुणिमा श्रीवास्तव, तहसीलदार सचिंद्र शुक्ला, दमकल विभाग के प्रभारी चौहान गौतम सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी व काफी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य मौजूद रहे।

# यूपी बोर्ड मुख्यालय में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की गई निगरानी

प्रयागराज, संवाददाता। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटर के 168 परीक्षा केंद्रों पर खामियां मिली हैं। बोर्ड मुख्यालय में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से दो दिन की निगरानी के बाद इन्हें चिह्नित किया गया। अब जांच कर इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने बताया कि इन केंद्रों के स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी और डीवीआर ऑफलाइन पाए गए। कई जगह सीसीटीवी की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। गाजीपुर में सबसे अधिक 15, जौनपुर में 13 और प्रयागराज के आठ केंद्रों के स्ट्रॉन्ग रूम में ये समस्याएं मिलीं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002

RNI सन्दर्भ संख्या - 24/234/2019/R/-1

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।